पर्यावरण मानदंड लागू करें पर लाइसेंस राज न लौटे : पीएम

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पर्यावरण अनुकूल प्रगति की वकालत करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि पर्यावरण को क्षति पंहुचाने से रोकने के लिए उचित नियामक मानदंड लागू करना चाहिए। हालंकि उन्होंने साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि लाइसेंस-परमिट राज न लौटने पाए।

सिंह ने कहा कि मानदंडों का उल्लंघन करके प्रदूषण फैलाने वालों से कीमत वसूलने का सिद्धांत भी लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि मानदंड बनाना ही काफी नहीं है। उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए, जो अक्सर मुश्किल होता है।' दिल्ली सतत विकास शिखर बैठक 2011 के उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि किसी भी सतत विकास को सुनिश्चित करने की रणनीति का केंद्रीय सिद्धांत यह है कि आर्थिक पहलुओं का फैसला करने वाले सभी लोगों या संगठनों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे पर्यावरण अनुकूल बातों को हमेशा ध्यान में रखें।

▶ जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा, औद्योगिक देशों को उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता जतानी चाहिए

इस शिखर बैठक में अन्य विशेषज्ञों के अलावा अफगानिस्तान, डोमिनिकन रिपब्लिक और सेशल्स के राष्ट्रपति भी हिस्सेदारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वाली करोड़ों डॉलर की कई बड़ी परियोजनाओं को लाल झंडी दिखाई है। सिंह ने कहा, हमें ऐसी ढांचागत नियामक नितियां बनानी होंगी जो पर्यावरण को क्षति पंहुचाने वाले आचरण पर रोक लगा सके। नियामक मानदंडों को बनाकर और उन्हें लागू करके हम ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि औद्योगिक देशों को उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों को पाने की पक्की प्रतिबद्धतता जतानी चाहिएं जिससे कोपेनहेगन जलवायु शिखर सम्मेलन में तय किए गए लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। भारत, चीन और कई अन्य विकासशील देशों ने प्रदूषण उत्सर्जन में कटौती लाने के लिए स्वैच्छिक लक्ष्य और विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं। प्रधानमंत्री ने खेद प्रकट किया कि औद्योगिक देशों की ओर से अभी तक इस दिशा में कोई ठोस आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है।